

90th General Assembly of INTERPOL

INTERPOL (The International Criminal Police Organization) is the world's largest international police organization and an inter-governmental organization with 195 member countries. Headquartered in Lyon, France, INTERPOL was founded in 1923 as the International Criminal Police Commission (ICPC); the name INTERPOL served as the agency's telegraphic address in 1946, and was chosen as its common name in 1956.

Globally, the increasing frequency of crimes with transnational linkages requires closer coordination among law enforcement agencies. There is a daily inflow and outflow of communications between National Central Bureaux of member countries which ranges from a compassionate request to locate and notify the next-of-kin of deceased; request to search for a missing person; criminal history requests; requests from law enforcement agencies for informal assistance in cases of fraud, commercial crime, trafficking in narcotics drugs, and criminal code offences.

Member countries of INTERPOL promote the widest possible assistance between all criminal police authorities in the prevention and suppression of ordinary law crimes. Its role is to enable police around the world to work together to make the world a safer place. Its high-tech infrastructure of technical and operational support helps meet the growing challenges of fighting crime in the 21st century. INTERPOL works to ensure that police around the world have access to the tools and services necessary to do their jobs effectively.

INTERPOL provides targeted training, expert investigative support, relevant data and secure communication channels. It also provides its member countries with instant, direct access to a wide range of criminal databases, containing millions of records on fingerprints, DNA, stolen motor vehicles, firearms, stolen and lost travel documents and more.

The General Assembly is INTERPOL's supreme governing body, comprising of representatives from each of 195 member countries. It meets once a year. Each member country may be represented by one or several delegates who are typically Ministers, Chiefs of Police, Heads of INTERPOL NCBx and senior ministry officials. Its purpose is to ensure that INTERPOL's activities correspond to the needs of member countries.

The General Assembly reviews and approves the programme of activities and financial policy for the coming year. In addition, the General Assembly elects the members of the Executive Committee, the governing body which provides guidance and direction in between sessions of the Assembly. The General Assembly takes decisions in the form of Resolutions. Each member country has one vote. The decision-making process is either by a simple or two-thirds majority, depending on the subject matter.

India is one of the oldest members of Interpol, having joined the organization in 1949. The Central Bureau of Investigation is designated as the National Central Bureau of India for INTERPOL. The Director of the Central Bureau of Investigation is the ex-officio Head of the INTERPOL National Central Bureau-New Delhi

India is an active member and has earlier hosted an Inter-Regional Meeting of Heads of Drug Services in 1988, the first Interpol Conference on Methaqualone in 1992, the 13th Asian Regional Conference in 1994, the 66th General Assembly Session of ICPO-Interpol in 1997 and the Sixth Global Focal Point Conference on Asset Recovery in 2015.

India hosted the 90th General Assembly of INTERPOL from 18th-21st October, 2022 at Pragati Maidan Venue, New Delhi, culminating with celebrations for 75th year of India's independence. The INTERPOL Flag was handed over to India on 25th November, 2021 during 89th INTERPOL General Assembly in Istanbul, Turkey.

To mark the 100th anniversary of the foundation of Interpol in Vienna, the annual General Assembly of the organization will take place in Vienna in 2023

Department of Posts is pleased to issue the Commemorative Postage Stamp on 90th General Assembly of INTERPOL in New Delhi and appreciates its role in international policing.

Credits:

Stamp/ FDC/ Brochure/: Mrs. Bharati Mirchandani

Cancellation Cachet : Mrs. Nenu Gupta

Text : Referenced from the contents provided by the proponent

विवरणिका
BROCHURE



इंटरपोल की 90वीं महासभा 90th General Assembly of INTERPOL



INTERPOL

इंटरपोल की 90वीं महासभा

इंटरपोल (अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन), विश्व का विशालतम अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। यह एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है, जिसके 195 सदस्य देश हैं। 1923 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (आईसीपीसी) के रूप में स्थापित इंटरपोल का मुख्यालय लियॉन, फ्रांस में स्थित है। 1946 में इस एजेंसी के टेलीग्राफिक पते के रूप में 'इंटरपोल' शब्द का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात् 1956 में इस एजेंसी को सामान्य रूप से इंटरपोल के नाम से जाना जाने लगा।

एक से अधिक देशों से जुड़े अपराधों की बढ़ती संख्या के कारण विश्वभर की कानूनी एजेंसियों में बेहतर समन्वय जरूरी है। इंटरपोल के सदस्य देशों के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के बीच सूचनाओं का दैनिक रूप से आदान-प्रदान होता है, जिसमें मृत्यु के मामले में निकट संबंधी को खोजना तथा उन्हें सूचित करना, किसी लापता व्यक्ति की तलाश करना, आपराधिक इतिहास से संबंधित अनुरोध, जालसाजी अथवा व्यावसायिक अपराध के मामले में अनौपचारिक सहयोग, नशीले पदार्थों की तस्करी एवं अपराध संहिता संबंधी मामलों से जुड़े अनुरोध शामिल होते हैं।

इंटरपोल के सदस्य देश, सामान्य अपराधों को रोकने तथा कम करने की दिशा में सभी आपराधिक पुलिस प्राधिकरणों के बीच यथासंभव व्यापक सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। इंटरपोल का उद्देश्य विश्वभर के पुलिस संगठनों को मिलकर काम करने में सक्षम बनाना है, ताकि विश्व में सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हो। इंटरपोल का उच्च कोटि का तकनीकी एवं प्रचालनात्मक इन्फ्रास्ट्रक्चर, 21वीं सदी में अपराध की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। इंटरपोल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि विश्वभर के पुलिस संगठनों को अपना कार्य सुचारु रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण तथा सेवाएं उपलब्ध हों।

इंटरपोल, विशिष्ट प्रशिक्षण, विशेषज्ञता आधारित जांच सहायता, संबंधित डाटा और संचार के सुरक्षित माध्यम मुहैया कराता है। इंटरपोल, अपने सदस्य देशों को अपराध एवं अपराधियों संबंधी विशाल डाटाबेस भी उपलब्ध करवाता है, जिसमें करोड़ों फिंगर प्रिंट्स, डीएनए, चोरी हुए मोटर वाहन, हथियार, चोरी और गुम हुए यात्रा दस्तावेजों आदि का संग्रह शामिल है।

इंटरपोल की महासभा, इसकी सर्वोच्च गवर्निंग इकाई है। इसमें सभी 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। महासभा की बैठक वार्षिक रूप से होती है। प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व उसके एक या एक से अधिक सदस्यों वाले विशिष्ट मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सामान्यतः मंत्रीगण, पुलिस संगठनों के प्रमुख, इंटरपोल एनसीबी के प्रमुख तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल होते हैं। महासभा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इंटरपोल के कार्यकलाप, इसके सदस्य देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

महासभा, आगामी वर्ष के लिए कार्यकलापों तथा वित्तीय नीतियों के कार्यक्रम की समीक्षा कर इसे अनुमोदन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, महासभा द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव भी किया जाता है। कार्यकारी समिति वह शासी इकाई है, जो सभा के दो सत्रों के बीच की अवधि में मार्गदर्शन एवं निर्देशन का कार्य करती है। महासभा, संकल्पों के रूप में निर्णय लेती है। प्रत्येक सदस्य देश का एक वोट निर्धारित है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए सामान्य बहुमत अथवा दो-तिहाई बहुमत द्वारा पूरी की जाती है।

भारत, 1949 से इंटरपोल का सदस्य है और इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। भारत की ओर से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो – नई दिल्ली के पदेन अध्यक्ष हैं।

भारत इंटरपोल का एक सक्रिय सदस्य रहा है। भारत, 1988 में ड्रग्स सेवा संगठनों के प्रमुखों की अंतर-क्षेत्रीय बैठक, 1992 में मेथाक्वेलोन पर प्रथम इंटरपोल कांफ्रेंस, 1994 में 13वीं एशियाई क्षेत्रीय कांफ्रेंस, 1997 में आईसीपीओ-इंटरपोल के 66वें महासभा सत्र और 2015 में 'एसेट रिकवरी' पर छठी ग्लोबल फोकल प्वाइंट कांफ्रेंस की मेजबानी कर चुका है।

भारत, ने 18 से 21 अक्तूबर, 2022 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है। भारत को इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित 89वीं इंटरपोल महासभा के दौरान 25 नवंबर, 2021 को इंटरपोल ध्वज सौंपा गया था।

इंटरपोल की वियना में स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, इस संगठन की वार्षिक महासभा 2023 में वियना में आयोजित की जाएगी।

डाक विभाग, अंतरराष्ट्रीय पुलिस व्यवस्था में इंटरपोल के योगदान को रेखांकित करते हुए 'इंटरपोल की 90वीं महासभा' विषय पर स्मारक डाक-टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :

डाक-टिकट/प्रथम दिवस : श्रीमती भारती मीरचंदानी
आवरण/विवरणिका
विरूपण केशे : श्रीमती नीनू गुप्ता
पाठ : प्रस्तावक द्वारा प्रदान की सामग्री से संदर्भित

तकनीकी आंकड़े

TECHNICAL DATA

मूल्य	: 500 पैसे
Denomination	: 500 p
मुद्रित डाक-टिकटें	: 305100
Stamps Printed	: 305100
मुद्रण प्रक्रिया	: वेट ऑफसेट
Printing Process	: Wet Offset
मुद्रक	: प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	: Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00